ACHIEVER IAS ACADEMY

SUMMERY OF THE HINDU

HINDI

20/05/2023

TALK TO US

+918434931877, +917250667974

achieveriaspatna@gmail.com

www.achieveriaspatna.co.in

NEW PATLIPUTRA COLONY ROAD NO. 4A, NEAR TENNIS COURT, PATNA-13

हिन्दू 20-05-23

राष्ट्रीय

⇨ हिंडनबर्ग-अडानी मामला: विशेषज्ञ पैनल ने सेबी को मंजूरी दी

SC ने SBI के कामकाज को देखने के लिए जस्टिस ए.एम. सप्रे की अध्यक्षता में एक छह सदस्यीय पैनल का गठन किया था, और इसकी ओर से की गई लापरवाही के कारण अडानी-हिंडनबर्ग गाथा हुई जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। पैनल ने सेबी को अपनी 178 पेज की रिपोर्ट पैनल में मुख्य निष्कर्षों को मंजूरी दे दी है: -

- न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता पर
  सेबी को 13 विदेशी संस्थाओं पर अडानी समूह के प्रवर्तकों के साथ संबंध होने का संदेह था। लेकिन सेबी इन्हें साबित नहीं कर सका और अधिक जांच की आवश्यकता है जो चल रही है।
- a/c न्यूनतम सार्वजनिक शेयर होल्डिंग नियम एक सूचीबद्ध कंपनी के कम से कम 25% शेयर जनता के लिए खुले होने चाहिए, जबकि 75% तक प्रमोटरों के पास हो सकते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी समूह कई शेयरों को सार्वजनिक होल्डिंग के रूप में दिखाता है, जिस पर अडानी का ही स्वामित्व है।
- संबंधित पार्टी लेनदेन पर
  संबंधित पक्ष लेन-देन - यह दर्शाता है कि दो पक्षों के बीच एक सौदे में पहले से मौजूद व्यापारिक संबंध या सामान्य हित थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में 600 से ज्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कमेटी का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सेबी अभी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की जांच कर रहा है।
- मूल्य हेरफेर पर।
  पैनल ने कहा कि शेयरों में मूल्य वृद्धि में जोड़-तोड़ योगदान का कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं पाया गया है, यह आरोप लगाया गया था कि सेबी ने नहीं किया, लेकिन सेबी के कार्रवाई नहीं करने के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। सेबी हेरफेर संकेतों पर सक्रिय था।

SC ने अडानी जांच पूरी करने के लिए सेबी को अगस्त तक का समय दिया है।
आरबीआई 2000 के नोट को सक्रिय संचलन से बाहर करेगा।
आरबीआई ने "क्लीन नोट पॉलिसी" के तहत 2000 के नोटों को बाजार परिसंचरण से वापस लेने का फैसला किया।

⇨ स्वच्छ नोट नीति - आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि ग्राहकों को गंदे, जालीदार और कटे-फटे नोट न दें स्वच्छ नोट नीति उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट देना है।

- कोई अपने बैंक खाते में 2,000 के नोट जमा कर सकेगा या 2,000 के नोट को बैंक के अन्य नोटों से बदल सकेगा।
- अभ्यास की आरंभ तिथि 23 मई और समाप्ति तिथि 30 सितंबर होगी।

- एक बार में 20,000 के 2000 के नोट जमा या बदले जा सकेंगे। लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए आरबीआई ने बैंक को गाइडलाइंस जारी की है। 23 मई से 30 सितंबर के बीच 2,000 के नोट अभी भी लेनदेन के लिए मान्य हैं।

⇨ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सुरक्षित रखा, नौकरशाहों पर एल-जी अंतिम राय देता है।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार में सेवारत सभी नौकरशाहों की पोस्टिंग और ट्रांसफर पर अंतिम निर्णय लेने वाले लेजियूटर-गवर्नर (एल-जी) को नामित करने वाला एक अध्यादेश लाया।

अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीए) अधिनियम, 1991 में संशोधन करना चाहता है। अध्यादेश के अनुसार

राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (NCCSA) की स्थापना की जाएगी जो सिविल सेवकों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर निर्णय लेगी।

NCCSA की अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे, जिसमें NCT दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव अन्य दो सदस्य होंगे।

सभी मामले उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से तय किए जाएंगे।

अध्यादेश में कहा गया है कि एल-जी एनसीसीएसए के फैसलों को प्रभावी करने के लिए आदेश देगा, लेकिन एनसीसीएसए के फैसले के संबंध में प्रासंगिक सामग्री मांग सकता है।

यदि एल-जी निर्णय से भिन्न है तो वह पुनर्विचार के लिए सिफारिशों को वापस कर सकता है।

मतभेद को ध्यान में रखते हुए उपराज्यपाल पर निर्णय अंतिम होगा।

इससे पहले 11 मई को SC ने अपने आदेश में कहा था कि पोस्टिंग, ट्रांसफर और अन्य नीतिगत मुद्दों पर दिल्ली कैबिनेट फैसला लेगी. और एलजी को अपनी सहमति देनी होगी

SC ने पूर्व सांसद की छूट के रिकॉर्ड मांगे।

SC ने शुक्रवार को बिहार सरकार को उन मूल दस्तावेजों को पेश करने का निर्देश दिया, जिनके कारण पूर्व सांसद आनंद मोहन की उम्रकैद की सजा को माफ करने का फैसला किया गया था।

आनंद मोहन एक आईएएस अधिकारी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा का सामना कर रहे थे

बिहार सरकार ने 10 अप्रैल को बिहार जेल नियमावली में संशोधन किया, जिसके अनुसार मारे गए अधिकारी के परिवार के सदस्यों के लोक सेवक की हत्या के मामले में 14 साल बाद छूट की अनुमति दी गई थी।

⇨ सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में 'शिवलिंग' पर वैज्ञानिक सर्वेक्षण टाला।

सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद की कार्बन डेटिंग कराने के कोर्ट के 12 मई के निर्देश पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

12 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था.

सीजेआई डाय चंदचूड ने कहा कि "12 मई के आदेश के कार्यान्वयन के लिए बारीकी से जांच की आवश्यकता होगी" अदालत ने अगली सुनवाई तक एएसआई द्वारा कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक अध्ययन को निलंबित कर दिया है।

⇨ **अनुसूचित जाति की स्वतंत्रता कानून के शासन का अभिन्न अंग है' जोसेफ।**

"सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक जीवन शैली के रखरखाव और एक कानून के शासन का अभिन्न अंग है। यह एक राष्ट्र के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, जो एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र के ठीक विपरीत चुनोती में फिसल जाता है।

- ⇨ **CJI द्वारा दो नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाए जाने के साथ ही SC अपनी गिरती हुई 34 की शक्ति पर वापस आ गया है**
- ⇨ **CJI ने जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और के.वी. विश्वनाथ के रूप में नए एससी न्यायाधीश के रूप में दो न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और एमआर शाह की जगह लेंगे जो पहले मई में सेवानिवृत्त हुए थे।**
- ⇨ **अडानी बैगस को क्लीन चिट के रूप में पैनल के निष्कर्षों को स्पिन करने का प्रयास: सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कांग्रेस के 6 सदस्यों के पैनल ने सेबी को किसी भी दुस्साहस से मुक्त कर दिया है।**
- ⇨ **यहां तक कि सीमित आर्सेनिक एक्सपोजर भी संज्ञानात्मक क्षमता को खराब कर सकता है: अध्ययन।**

जामा नेटवर्क ओपन के एक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि आर्सेनिक के 10 वी स्तर का सेवन भी बच्चों, किशोरों और युवा वयस्कों में संज्ञानात्मक कार्य को प्रभावित कर सकता है। अध्ययन में पाया गया कि आर्सेनिक के संपर्क में आने वालों ने ग्रे मैटर (संज्ञानात्मक कार्य के लिए आवश्यक मस्तिष्क के ऊतक) को कम कर दिया था और मस्तिष्क में कमजोर कनेक्शन जो एकाग्रता राशन को सक्षम बनाता है।

दूषित भूजल से उच्च स्तर के आर्सेनिक की खपत को भारत में कई बीमारियों से जोड़ा जा रहा है

- ⇨ **'इस बार, मेरा एक सपना था'**

कमांडर (सेवानिवृत्त) अभिलाष टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस (जीजीआर) में दूसरे स्थान पर रहे। GGR 1960 के दशक में नौकायन को फिर से बनाने के लिए बिना किसी आधुनिक तकनीकी सहायता के ग्लोब का एकल नॉन-स्टॉप सर्कविगेशन है। दौड़ में 11 देशों के 16 प्रतिभागी थे।

दुनिया

- ⇨ **ईवी के शीर्ष अधिकारी रूसी तेल से प्राप्त भारतीय उत्पादों पर अधिक जांच चाहते हैं।**
  ईवी के शीर्ष विदेशी मामलों और सुरक्षा अधिकारी जेसप बोरेल ने एक ब्लॉग में कहा।
    - भारतीय तेल खरीद यूक्रेन संकट से पहले .2% से यूक्रेन संकट के बाद 36.4% तक बढ़ गई है
    - यूरोपीय कंपनियों द्वारा भारत से तेल उत्पाद खरीदने की संख्या में वृद्धि हुई है। यह रूसी तेल खरीद पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन है।

      कुछ दिनों पहले ईएएम एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा था कि (ईवी) को भारत से परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करना है।
- ⇨ **पाकिस्तान के अधिकारियों ने इमरान को 2,200 वांछित लोगों की सूची सौंपी।**

पंजाब प्रांत सरकार के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने इमरान खान से उनके जमां पार्क स्थित आवास पर मुलाकात की। उन्होंने श्री खान को 2200 संदिग्धों की एक सूची सौंपी जो लाहौर कॉर्प्स कमांडर हाउस और अस्करी टॉवर पर हमले में शामिल थे। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, श्री खान ने

9 मई की हिंसा में उनकी पार्टी की भागीदारी के बारे में सबूत मांगे, यह कहते हुए कि अगर पीटीआई से कोई भी शामिल था, तो "मैं उन्हें पकड़ने में मदद करूंगा"

शुक्रवार को एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने आतंकवाद के तीन मामलों में श्री खान को 2 जून तक गिरफ्तारी पूर्व जमानत दे दी।

⇨ **यू.एस. यूक्रेन को उन्नत जेट, पायलट प्रशिक्षण प्रदान करेगा।**

व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को जी-7 नेताओं से कहा कि वाशिंगटन यूक्रेन को एफ-16 सहित उन्नत युद्धक विमान उपलब्ध कराने का समर्थन करेगा और यूक्रेन के पायलटों को प्रशिक्षित करने के प्रयासों का समर्थन करेगा।

यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोडमिर ज़ेलेंस्की ने इस कदम को "ऐतिहासिक" बताया है

पहले ब्रिटेन। यूक्रेन को क्रूज मिसाइल देने का करार किया था।

F-16 – यह वर्तमान में सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक है। सुखोई, राफेल के अनुरूप पड़ता है

⇨ **ईरान ने पिछले वर्षों के अमिनी विरोध से जुड़े तीन लोगों को फांसी दी।**

उन्हें इस्फ़हान में विरोध के दौरान बंदूक खींचने के लिए "भगवान के खिलाफ युद्ध" का दोषी ठहराया गया है।

⇨ **सऊदी की मेजबानी वाले शिखर सम्मेलन में सीरिया की असद टोपी अरब समूह में वापस आ गई**

“अरब नेता ने अरब लीग में सीरिया का स्वागत किया, इस साल जेद्दा, सऊदी अरब में मेजबानी की।

⇨ **रूस ने बराक ओबामा सहित 500 अमेरिकी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।**

संपादकीय-1

अच्छा परिवर्तन

कानून मंत्रालय से रिजिजू को स्थानांतरित करने से न्यायपालिका के साथ संघर्ष समाप्त होना चाहिए

⇨ **संपादकीय किस बारे में है?**

संपादकीय हालिया कैबिनेट फेरबदल के बारे में है जिसमें किरण रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटा दिया गया था। संपादकीय किरण रिजिजू को हटाने के संभावित कारणों और राज्य के नए कानून मंत्रालय के समक्ष चुनौतियों के बारे में बताता है

⇨ **हाल के कैबिनेट फेरबदल के बारे में।**

किरण रिजिजू को कानून और न्याय मंत्री के पद से हटा दिया गया है। उन्हें अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है।

अर्जुन राम मेघवाल स्वतंत्र प्रभार वाले कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं

	नया	पुराना
	↓	↓
कानून मंत्रालय और न्याय →	कोई कैबिनेट मंत्री नहीं लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ	किरण रिजिजू कैबिनेट मंत्री

		अर्जुन राम मेघवाल पर आरोप
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	किरण रिजिजू कोई कैबिनेट मंत्री	कैबिनेट मंत्री नहीं

⇨ **कानून मंत्री के पद से किरण रिजिजू को हटाने का संभावित कारण क्या था?**

- श्री रिजिजू के कार्यकाल में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष में वृद्धि देखी गई।
- श्री रिजिजू न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के आलोचक थे। उन्होंने सार्वजनिक मंच पर कई बार अपनी आलोचना व्यक्त की।

⇨ **स्टॉक के नए कानून मंत्री के सामने ☐ चुनौतियां**

श्री मेघवाल ने अपना कार्यकाल इस तरह शुरू किया कि वे न्यायपालिका के साथ कोई संघर्ष नहीं चाहते थे, उन्होंने कार्यालय में पहले दिन एससी के लिए 2 न्यायाधीशों को मंजूरी दे दी।

न्यायिक नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया के नए ज्ञापन को अंतिम रूप देना सरकार ने SC को प्रक्रिया के ज्ञापन को अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया था।

सरकार। "प्रवंचना सह मूल्यांकन समिति" का विचार दिया था जिसमें एक सरकारी प्रतिनिधि वे होंगे।

ये कुछ जरूरी मुद्दे हैं।

कोई कैबिनेट मंत्री नहीं	कैबिनेट मंत्री
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री	
यानी राज्य मंत्री से ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं	

ACHIEVERS IAS ACADEMY

संपादकीय-2

अभिजात वर्ग के बीच

G-20 की भारत की अध्यक्षता इसे G-7 शिखर सम्मेलन में अतिरिक्त महत्व देती है

⇨ **संपादकीय किस बारे में है?**

पीएम मोदी हिरोशिमा में जी-7 में हिस्सा लेने वाले हैं. भारत के पास जी-20 की अध्यक्षता है। संपादकीय जी-7 बैठकों में भारत का रुख और प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है।

⇨ **जी-7 के बारे में**

G-7 7 देशों और EV (यूरोपीय संघ) का समूह है

G-7 सदस्य → यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, जापान, कनाडा + ईयू (यूरोपीय संघ)

इस साल G7 की मेजबानी हिरोशिमा (जापान) कर रहा है।

हिरोशिमा वही शहर है जहां विश्व युद्ध के अंत में यूएसए बालक ने अपना पहला परमाणु बम गिराया था। अन्य देश जिन्हें इस बार जी-7 के लिए आमंत्रित किया गया है वे हैं: भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोमोरोस और कुक आइलैंड, यूक्रेन।

⇨ **भारत और जी-7**

भारत ने G-20 कार्यक्रम को G-7 कार्यक्रम के साथ संरेखित किया है, जिसका अर्थ है कि दोनों में प्रमुख मुद्दे एक ही निर्माण आपूर्ति श्रृंखला विश्वसनीयता होंगे जो वैकल्पिक आपातकालीन गठबंधन की अगुआई करेंगे और वैकल्पिक ऊर्जा गठबंधन की मांग कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की

जाएगी। यूक्रेन का मुद्दा प्रमुख मुद्दों में से एक होगा, जबकि भारत ने खुद को रूस और पश्चिम के बीच संतुलित कर लिया है। G-7 के सभी सदस्य रूस के प्रति सख्त हैं, वे आगे की कार्रवाई करते दिख रहे हैं जो आगे की कार्रवाई करते दिख सकते हैं जो रूसी अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचा सकते हैं।

भारत को यहां अपने रुख पर कायम रहना होगा।

भारत "वैश्विक दक्षिण की आवाज" का प्रतिनिधित्व करता है, और उसे खाद्य, उर्वरक और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्रों में विकासशील देशों पर जी-7 देशों द्वारा प्रतिबंध हटाने की वकालत करनी होगी।

पीएम मोदी यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी मुलाकात कर सकते हैं।

G-7 के मौके पर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत के बीच QUARD की बैठक होने की उम्मीद है।

The ACHIEVERS IAS ACADEMY